कृपया प्रकाशनार्थ - **21 अप्रैल 2011**

पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक द्वारा गुरुवार, 21 अप्रैल 2011 को पाटना में पत्रकार परिषद में प्रसारित वक्तव्य

पेट्रोलियम नीति बनाएं
सिलंडर की किल्लत रोकें

पाटना, गुरुवार : "महंगाई और भ्रष्टाचार आज देश की सबसे दो बड़ी समस्याएं हैं. पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते किमतों के कारण महंगाई और भी बढ़ रही है. महंगाई के इस दुष्ट चक्र को तेज गति प्राप्त हुई है. जबरदस्त राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो ही प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह इसे रोक सकेंगे. इस लिए सबसे ज्यादा जरुरी बात है पेट्रोलियम की नीति बनाना और उस का कार्यान्वयन करना," ऐसा पूर्व पेट्रोलियम मंत्री तथा भाजपा नेता श्री. राम नाईक ने आज पाटना में पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा.

अपनी बात को स्पष्ट करते हुए श्री. राम नाईक ने कहा, " भारत अपनी जरुरत के 70 प्रति शत कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) विदेशों से आयात करता है. वैसे भी आंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की किमतों में काफी उछल - पुछल होती हैं जिसका सीधा परिणाम हमारी वित्त व्यवस्था पर होता है. इस परिस्थिती में अपनी वित्त व्यवस्था को तथा ग्राहकों को कम से कम तकलीफ हो इसलिए हमें सुस्पष्ट पेट्रोलियम नीति की आवश्यकता है. फिलहाल पेट्रोल पर आयात कर, आबकारी कर, विक्री कर आदी मिल कर लगभग 50 प्रतिशत तक अलग - अलग कर लागू किए जाते हैं; तो डिजल पर 33 प्रतिशत करों का बोझ है. इन करों को घटाने के लिए एक सुस्पष्ट पेट्रोलियम नीति बना कर उस का कार्यान्वयन करने की राजनीतिक इच्छाशक्ती का प्रदर्शन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने करना चाहिए. किंतु वास्तव में पिछले छः वर्षों में इस देश को तीन पेट्रोलियम मंत्री देकर प्रधानमंत्री ने उलटा अपनी कमजोरी का ही प्रदर्शन किया है."

"संपूर्ण देश में रसोई गैस की गंभीर किल्लत पैदा की गयी है. कईं जगहों पर तो सिलंडर मिलने के लिए ग्राहकों को एक महिने से भी अधिक दिन राह देखनी पडती हैं. वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में हमने 4 करोड़ नए ग्राहकों को रसोई गैस कनेक्शन दिए, इतनाहि नहीं तो अतिरिक्त दाम न लेते हुए हम 24 घंटों में नया सिलंडर देते थे. तो अब कौनसा पहाड टूटा हैं जिस के कारण सिलंडर की किल्लत हो रही है ? सब जगह खुले आम रसोई गैस सिलंडरों का कालाबाजार भी तेज हैं. पहाड़ी इलाकों में तथा जुग्गी - झोपडी में रहने वाले गरीबों के लिए हमने 5 किलो के घरेलु उपयोग के रसोई गैस सिलंडर बनवाए थे. अबकी कांग्रेस सरकार ऐसी है कि उन्होंने इन सिलंडरों को बंद करवा कर उनकी व्यावसायिक मूल्य पर विक्री शुरु की हैं. हालही में 18 मार्च को मैंने पेट्रोलियम मंत्री श्री. जयपाल रेड्डी को मिल कर इस बात की ओर उनका ध्यान खिंचा, फिर भी स्थिती में कोई बदलाव नहीं हैं," ऐसा भी श्री. राम नाईक ने कहा.

..2..

कांग्रेस सरकार के पास राजनीतिक इच्छाशक्ती की कितनी कमी है इसका उदाहरण अभी अभी महाराष्ट्र में दिखायी दिया. महाराष्ट्र में तेल माफियों को रंगेहाथ पकडने की कोशिश करनेवाले उपजिलाधिकारी श्री. सोनावणे को तेल माफियों ने जिंदा जला डाला. ऐसी दिल देहलानेवाली जानकारी देकर श्री. नाईक ने कहा, "जब मैं पेट्रोलियम मंत्री था तब पेट्रोल, डिजल की मिलावट को रोकने के लिए हमने पुरे देश में मिलावट प्रतिबंधक प्रकोष्ठ निर्माण कर मुहीम चलायी थी. प्रत्येक राज्य में इसकी शाखाएं भी स्थापित की थी. बार - बार छापा डाल कर मिलावट पर काफी रोक लगवाने में हम सफल हुए थे. मगर जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता पर आयी उन्होने यह प्रकोष्ठ ही तेल माफियों के दबाव में बंद कर डाला," ऐसी आलोचना भी श्री. नाईक ने की.

सुस्पष्ट नीति कैसी होती है यह कहते हुए श्री. राम नाईक ने कहा, "ब्राजिल में गन्ने की चासनी (मोलॅसिस) से इथेनॉल बनाया जाता है, जिसका पेट्रोल में मिला कर प्रयोग किया जाता है. अपने देश में भी काफी गन्ना पैदा होता हैं. कच्चे तेल की आयात कम हो तथा गन्ना - उत्पादक किसानों को भी लाभ हो इस दृष्टी से मैंने इथेनॉल बनाने का निर्णय लिया था. वर्ष 2001 में उत्पादन भी प्रारंभ हुआ. देश के सभी गन्ना उत्पादक राज्यों में पेट्रोल में 5 प्रतिशत इथेनॉल मिलाना शुरु हुआ. आगे चल कर यह मात्रा सभी राज्यों मे दस प्रतिशत तक बढानी थी. किंतु कांग्रेस सरकार ने लिकर लॉबी के सामने घुटने टेके और इथेनॉल मिलानाही बंद कर दिया. अब छः वर्षों के बाद फिर एक बार सरकार इस विषय पर विचार कर रही है. मगर सवाल यह है कि इन छः वर्षों में केवल किसानों का ही नही तो पुरे देश का जो नुकसान हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?" ऐसा सवाल भी श्री. राम नाईक ने अन्त में किया.

(कार्यालय मंत्री)